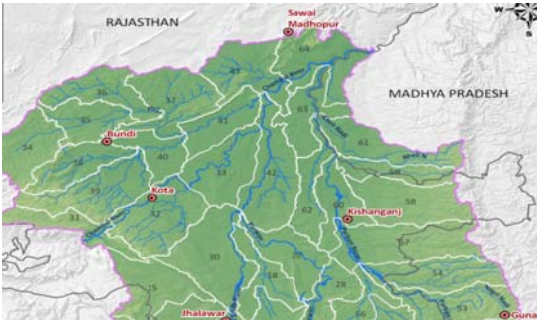


## पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)

### यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : पर्यावरण संबद्ध मुद्दे	द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र : सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

### संदर्भ



- केंद्र ने अन्य राज्यों द्वारा असहमति व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रस्तावित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) पर काम रोकने का निर्देश दिया है।
- विदित है कि राजस्थान लंबे समय से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग कर रहा है।

### विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

#### पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) क्या है?

- राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया था।
- इसके अंतर्गत पार्वती, चंबल और कालीसिंध नदी को जोड़ने की बात कही गई थी। साथ ही इस परियोजना के पूरा होने से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और कोटा में जल संकट का समाधान होने के साथ किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति किए जाने की बात कही जा रही थी।
- ज्ञातव्य है कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ईआरसीपी महत्वपूर्ण है।

#### राजस्थान में भूजल की वर्तमान स्थिति

- राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 342.52 लाख हेक्टेयर है, जो पूरे देश का 10.4 प्रतिशत है।

- राज्य जल संसाधन विभाग के अनुसार, राज्य में भारत के सतही जल का केवल 1.16 प्रतिशत और भूजल का 1.72 प्रतिशत है।
- राज्य के जल निकायों में केवल चंबल नदी के बेसिन में अधिशेष पानी है, किन्तु इस पानी का सीधे दोहन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोटा बैराज के आस-पास के क्षेत्र को मगरमच्छ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है।

### ईआरसीपी का उद्देश्य

- ईआरसीपी का उद्देश्य डायवर्सन संरचनाओं, इंटर-बेसिन जल अंतरण, लिंकिंग चैनलों और पंपिंग मुख्य फीडर चैनलों के निर्माण की सहायता से जल चैनलों का एक नेटवर्क बनाना है, जो राजस्थान के 23.67 प्रतिशत क्षेत्र को राज्य के 41.13 प्रतिशत आबादी के साथ कवर किया जाना था।

### परियोजना की घोषणा कब की गई?

- 2017-18 के बजट में राजस्थान में तत्कालीन वसुंधरा राजे के कार्यकाल में इसकी घोषणा की गई थी।
- इस परियोजना को 2017 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- अपने 2017-18 राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को ईआरसीपी को राष्ट्रीय महत्व वाली परियोजना के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था।
- तब से लगातार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की जा रही है।

### परियोजना के पूरा होने की अनुमानित अवधि और लागत

- 10 वर्षों में परियोजना के पूरा होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा था।
- प्रारम्भ में परियोजना को 2017 और 2023 के मध्य तीन चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव था।
- इसकी अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपये है।

## परियोजना के अनुमानित लाभ

- राजस्थान जल संसाधन विभाग के अनुसार, ईआरसीपी से 2 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त कमांड क्षेत्र बनाने का अनुमान था, जिससे राज्य के 4.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलने की संभावना थी।
- ईआरसीपी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार करने में सहायक होता और इन क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता।
- यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) पर विशेष बल देता है।
- इस परियोजना के पूरा होने से राज्य में टिकाऊ जल स्रोत के बढ़ने और उद्योगों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होता, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में निवेश और राजस्व में वृद्धि होती।

## निष्कर्ष

- 37,200 करोड़ रुपए की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे 13 जिलों की पेयजल आवश्यकताएं पूरी होंगी और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास होगा।
- केन्द्र सरकार की ओर से इस परियोजना को 90:10 के अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही थी।
- विदित है कि राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर ई.आर.सी.पी. को 10 वर्ष में पूर्ण किया जा सकेगा, जिससे प्रदेश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी की पेयजल समस्या का समाधान होगा।
- यद्यपि, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश की आपत्ति का निराकरण करने तक स्थगित करने का निर्देश दिया है।

स्रोत: द हिंदू

[भारत-ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी](#)

## यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : पर्यावरण संबद्ध मुद्दे	द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण

## संदर्भ



- ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

## विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

### पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जहां सभी पक्षों ने हरित और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया था।
- ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने 20-23 जून के दौरान भारत का दौरा किया।

### भारत-ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी

- ऑस्ट्रेलिया और भारत सोमवार ने महत्वपूर्ण धातु परियोजनाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने में पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक साझेदारी पर सहमति व्यक्त की है।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के प्रयास के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों में उनके उपयोग के कारण हाल के दिनों में लिथियम और कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण धातुओं की मांग बढ़ गई है।
- ऑस्ट्रेलिया तीन वर्ष के भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए 5.8 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है।
- भारतीय कंपनी और सीएमएफओ दोनों संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया की लिथियम और कोबाल्ट खनिज संपत्तियों में 6 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक राशि के साथ वित्तपोषित करेंगे।

### भारत और ऑस्ट्रेलिया सहयोग

- ऑस्ट्रेलिया विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।

- भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जी-20, राष्ट्रमंडल, आईओआर-एआरसी, आसियान क्षेत्रीय मंच, जलवायु और स्वच्छ विकास पर एशिया प्रशांत भागीदारी के सदस्य हैं और उन्होंने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया है।
- दोनों देश विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में पांच इच्छुक पार्टियों (एफआईपी) के सदस्यों के रूप में भी सहयोग कर रहे हैं।
- ऑस्ट्रेलिया एपेक में एक महत्वपूर्ण पक्ष है और संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है।
- 2008 में ऑस्ट्रेलिया को सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला।

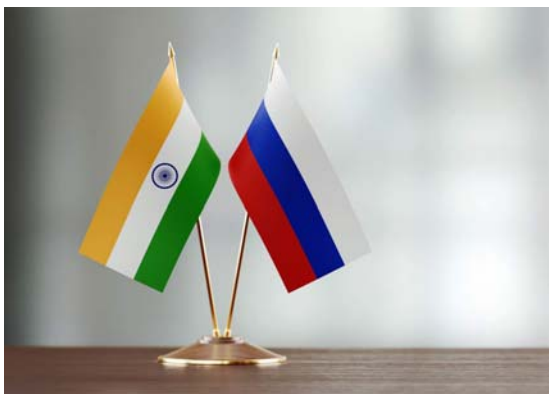
स्रोत: द हिन्दू

### भारत-रूस रक्षा सहयोग

#### यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	तृतीय प्रश्न पत्र : रक्षा

संदर्भ



- रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए।
- विदित है कि इससे रूस की पुर्जों और हार्डवेयर की समय पर आपूर्ति क्षमता के प्रभावित होने की संभावना को जन्म दिया है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

भारत-रूस रक्षा सहयोग की स्थिति

- 5.43 बिलियन डॉलर की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों सहित कुछ बड़े सौदों की पृष्ठभूमि में भारत और रूस के बीच रक्षा व्यापार 2018 के बाद से \$15 बिलियन के स्तर पर पहुँच गया है।

- वर्तमान में कार्यान्वयन के तहत अन्य प्रमुख अनुबंध रूस और भारत में चार अतिरिक्त स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें T-90S टैंकों के लिए मैंगो आर्मर-पियर्सिंग फिन-स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबोट (APFSDS) राउंड का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन और साथ ही अतिरिक्त T-90S टैंक, AK -203 असॉल्ट राइफलों आदि शामिल हैं।
- यद्यपि इसकी आपूर्ति में विलंब हो रही है। उदाहरण के लिए, S-400 की दूसरी रेजिमेंट की आपूर्ति में कुछ महीनों की देरी हो रही है और साथ ही उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरवा में 6.1 लाख AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए समझौते के संचालन में भी देरी हुई है।
- वर्तमान में कई बड़े रक्षा समझौतों के लिए वार्ता की जा रही है, लेकिन उनमें से कई को रक्षा मंत्रालय द्वारा सभी प्रत्यक्ष आयात सौदों की समीक्षा के हिस्से के रूप में स्थगित किया गया है।

### भारत-रूस रक्षा सहयोग बनाम अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास

- अमेरिकी थिंक टैंक 'स्टिमसन सेंटर' द्वारा वर्ष 2020 में प्रस्तुत किए गए आकलन के अनुसार, भारत के रक्षा उपकरणों में से रूस में बने हथियारों की हिस्सेदारी 86 फीसद है।
- वहीं वर्तमान में यूक्रेन संकट परिदृश्य में अमेरिका की ओर से सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के प्रयास कूटनीतिक स्तर पर तेज हो गई है।

### रक्षा खरीद में विविधता

- भारत विश्व के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में शामिल है।
- अमेरिकी थिंक टैंक 'स्टिमसन सेंटर' के अनुसार, भारत की रूस के हथियारों पर निर्भरता कम हुई है और अन्य देशों से भी हथियार खरीदे गए हैं।
- फ्रांस के अलावा इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से भी भारत ने हथियार खरीदे हैं, लेकिन इन हथियारों की मात्रा कम है।
- सिपरी के अनुसार, भारत ने वर्ष 2017 की तुलना में 2021 में फ्रांस, अमेरिका और इसराइल से दोगुने हथियार खरीदे।
- यद्यपि, अभी भी रूस ही भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
- अमेरिका के साथ भारत के सैन्य और सुरक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। वर्ष 2018-19 के बीच दोनों देशों के बीच रक्षा कारोबार में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

- भारत ने अमेरिका से लंबी दूरी के टोही विमान, मालवाहक विमान सी-130, मिसाइलें और ड्रोन खरीदे हैं।
- हाल में पेंटागन ने कहा कि भारत और अमेरिका अंतरिक्ष सुरक्षा और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।

### निष्कर्ष

- भारत मेक इन इंडिया नीति के तहत घरेलू स्तर पर हथियार बनाने पर बल दे रहा है। साथ ही अपने रक्षा उद्योग में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। किन्तु रक्षा मामले में रूस की महत्ता अभी भी विशिष्ट है।

स्रोत: द हिन्दू